दूध बेचने वाले किसानों की प्रोत्साहन राशि दोगुनी हुई

अब हर लीटर पर मिलेंगे छह रुपये; सरकार ने दे दी है मंजूरी, 14 करोड़ रुपये का बजट रखा



सुखविन्द्र सुक्खू • जागरण आर्काइव

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : प्रदेश में गैर-सरकारी डेरी सहकारी समितियों को दूध बेचने वाले पशुपालकों को अब प्रति लीटर दोगुना प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने दूध प्रोत्साहन राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी है।

योजना के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से पात्र दूध उत्पादकों के बैंक खातों में किया जाएगा। सरकार ने यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया है। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बोले-सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों के उत्थान के लिए दृढ़संकल्प, पात्र किसानों के बैंक खाते में जाएगी यह राशि

पशुपालन और दूध उत्पादन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है।

गैर-सरकारी डेरी सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को इन संस्थानों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समान प्रोत्साहन सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। पहले इसके तहत तीन रुपये प्रति लीटर दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर छह रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को जारी बयान में कहा कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए डेरी फार्मिंग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभकारी बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार किसानों की आर्थिकी मजबूत बनाने के लिए दृढ़संकल्प है। उन्होंने कहा कि दूध प्रोत्साहन राशि बढ़ने से पात्र पशुपालकों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था मजबूत करने के साथ सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर पांच स्कूलों को सीबीएसई करने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद प्रदेश के पांच और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इनमें शिमला जिले के चिड़गांव, धमवाड़ी, जांगला और तकलेच और किन्नौर जिले का कल्पा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में सत्र 2027-28 से सीबीएसई की कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य है। इससे यहां पढ़ रहे 1371 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

चिड़गांव, धमवाड़ी, जांगला, तकलेच और कल्पा स्कूल के 1371 विद्यार्थियों को मिलेगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से पढ़ने का अवसर



मुख्यमंत्री ने रोहड़ू, रामपुर और किन्नौर दौरे के दौरान इन स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिक्षा सचिव को कार्रवाई कर अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अब पांचों विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध करने के लिए स्वीकृति देने का आग्रह किया है। हालांकि नए सत्र से कक्षाएं शुरू होना सीबीएसई की संबद्धता मिलने पर निर्भर करेगा। इन पांचों स्कूलों में चिड़गांव में सबसे अधिक 411 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। जांगला में 325, धमवाड़ी में 268, तकलेच में 248 और कल्पा में 119 विद्यार्थी नामांकित हैं।

राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आज

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत आवास निर्माण और योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा होगी। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को राज्यस्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की दूसरी बैठक होगी। इसमें सभी प्रशासनिक सचिव भाग लेंगे। बैठक में योजना के तहत चल रहे कार्यों, आवासों की स्वीकृति, निर्माण की स्थिति और लाभार्थियों को मिल रहे लाभ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक सचिवालय में होगी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में पात्र परिवारों को नए आवासों को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता 2.25 लाख प्रति आवास और राज्य सरकार का न्यूनतम अंश 25,000 रुपये है।

पीएम ने बल्क ड्रग पार्क निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा

- पीएम गति शक्ति की प्रगति की समीक्षा के लिए आनलाइन बैठक में दिए निर्देश
- ढांचागत विकास और स्वीकृतियों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति की बुधवार शाम को प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय आनलाइन बैठक में प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और क्रियान्वयन एजेंसियों की कार्यप्रणाली के बारे में जाना।



नरेन्द्र मोदी • जागरण आर्काइव

उन्होंने निर्देश दिया कि ढांचागत विकास और स्वीकृतियों में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर कर परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर धरातल पर उतारा जाए। इसी माह हुई तैयारी बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्य सचिव केके पंत और प्रधान सचिव उद्योग एम सुधा देवी से भी इस विषय पर फीडबैक ली गई थी। प्रदेश सरकार को मार्च 2027 तक पार्क का निर्माण करना है, लेकिन इसमें देरी हो सकती है।

30 दिन में बैठक करने के निर्देश : समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और अंतर-विभागीय समन्वय को लेकर अहम दिशानिर्देश दिए। उन्होंने समयबद्ध कार्ययोजना और निगरानी के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को 30 दिन के भीतर भूमि हस्तांतरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और निर्माण के संशोधित लक्ष्य तय करने को कहा है। गति शक्ति पोर्टल के डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए प्रगति की पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्टीम जेनरेशन, टेस्टिंग लैब और वेयरहाउसिंग जैसी साझेदार सुविधाओं के टेंडर और निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा गया, ताकि निजी निवेशकों का भरोसा बना रहे।

निर्माण में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।



गुजरात और आंध्र प्रदेश में भी बन रहे हैं पार्क

केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन योजना के तहत हिमाचल सहित गुजरात और आंध्र प्रदेश के लिए वर्ष 2022 में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी थी। हिमाचल में ऊना के हरोली में उत्तर भारत के इस सबसे बड़े दवा पार्क के लिए भूमि समतलीकरण, विद्युत सब-स्टेशन और पानी की लाइन बिछाने के कार्य तेज गति से नहीं हो पा रहे हैं।

पेंशनरों ने एचआरटीसी मुख्यालय के घेराव की दी चेतावनी



राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 31 अक्टूबर तक सभी लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर तीन नवंबर से निगम मुख्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव करने की चेतावनी दी है। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी जारी रखी तो वे मुख्यालय के गेट पर दिवाली मनाने के लिए मजबूर होंगे।

वीरवार को समिति की बैठक पुराना बस अड्डा परिसर शिमला में हुई। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में केसी चौहान, बृजलाल ठाकुर, देवराज ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, देवेंद्र चौहान, नानक शांडिल, सुरेंद्र गौतम और अजमेर ठाकुर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने सरकार व निगम प्रबंधन से पेंशनरों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया।

पटाखों का शोर छोड़ो, खुशियों से रोशन करो यह दिवाली

- स्कूली बच्चे घर-घर पहुंचाएंगे ग्रीन दिवाली का संदेश, पटाखों का नुकसान भी बताएंगे
- शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी कर जागरूकता बढ़ाने को कहा

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : इस दिवाली पटाखों का शोर कम होगा, स्कूली बच्चों की आवाज ग्रीन दिवाली का संदेश देगी। बच्चे अपने परिवार और आसपास के लोगों को समझाएंगे कि त्योहार की खुशियां धुएं और तेज धमाकों की मोहताज नहीं हैं। इसके लिए पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। दिवाली पर पटाखों का धुआं हवा की गुणवत्ता बिगाड़ता है, जबकि तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और पशु-पक्षियों के लिए परेशानी का कारण बनती है। विद्यार्थियों को इन दुष्प्रभावों की जानकारी देकर पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बच्चे खुद जागरूक होंगे और अपने घरों में भी ग्रीन दिवाली का संदेश पहुंचाएंगे।

शिक्षा विभाग की इस पहल में विद्यार्थी जागरूकता की कड़ी बनेंगे। वे स्वजन और आसपास के लोगों को बताएंगे कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्देश्य है कि दिवाली की खुशियां बरकरार रहें और ध्वनि व वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लोग अपनी जिम्मेदारी समझें।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना जरूरी

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने उप निदेशकों को पत्र जारी कर स्कूल प्रमुखों को आवश्यक निर्देश देने को कहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी पत्र का हवाला दिया गया है। बोर्ड ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, निर्धारित ध्वनि सीमा और वायु गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

15 नवंबर को धर्मशाला में जुटेंगे 30 हजार शिक्षक

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। संघ 15 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदर्शन करेगा। इसमें करीब 30 हजार शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, जेबीटी व एनटीटी प्रशिक्षित बेरोजगार, मिड-डे मील वर्कर, मल्टीटास्क वर्कर, एसएमसी सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि शामिल होने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले प्रदेश के सभी 68 विधायकों को मांगपत्र सौंपे जाएंगे।

वहीं संघ का शिमला स्थित निदेशालय, स्कूल शिक्षा परिसर में क्रमिक अनशन वीरवार को 96वें दिन भी जारी रहा। करवाचौथ के दिन भी शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर डटे रहे। किन्नौर जिला के कल्पा ब्लाक के अध्यक्ष संत कुमार नेगी, महासचिव श्याम सुंदर, कोषाध्यक्ष यशवीर नेगी और सहसचिव राजेश्वर नेगी शामिल रहे।

प्रोफेसर वेपा राव स्मृति व्याख्यान कल उपमुख्यमंत्री मुकेश होंगे मुख्य अतिथि

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला : वरिष्ठ पत्रकार एवं द स्टेट्समैन के पूर्व संपादक राजू संथानम 31 अक्टूबर को शिमला के गेयटी थियेटर स्थित गाथिक हाल में प्रथम प्रोफेसर वेपा राव स्मृति व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। यह स्मृति व्याख्यान पत्रकारिता शिक्षाविद् प्रोफेसर वेपा राव की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। प्रोफेसर राव ने एचपीयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का लगभग तीन दशकों तक नेतृत्व किया और मीडिया जगत में पत्रकारों का मार्गदर्शन किया। व्याख्यान का आयोजन प्रोफेसर वेपा राव के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा एचपीयू के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग तथा ककिली चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है।



स्व. प्रोफेसर वेपा राव • जागरण

एसओएस परीक्षा केंद्र के लिए पहली से आवेदन कर सकेंगे निजी स्कूल

- मार्च 2027 में आयोजित होंगी परीक्षाएं, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल
- 30 नवंबर के बाद आवेदन पर शुल्क के अलावा विलंब शुल्क भी लिया जाएगा

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2027 में प्रस्तावित राज्य मुक्त विद्यालय (एसओएस) की परीक्षाओं के सुचारु और नकलरहित संपन्न कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने संबद्ध निजी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को एसओएस परीक्षा केंद्र के रूप में नामित करने के लिए आनलाइन आवेदन की तिथियां घोषित कर दी हैं। इच्छुक संस्थान एक नवंबर से बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूल लागिन आइडी से आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन करने वाले संस्थानों से निर्धारित शुल्क के अलावा विलंब शुल्क भी लिया जाएगा।

बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि बिना विलंब शुल्क के एक से 30 नवंबर तक आनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एक से 15 दिसंबर के बीच आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 5,000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। 16 से 31 दिसंबर तक विलंब शुल्क बढ़कर 10,000 हो जाएगा। यदि कोई संस्थान 31 दिसंबर की अंतिम तिथि के बाद आवेदन करता है तो उस पर केवल बोर्ड के अध्यक्ष या सचिव की स्वीकृति के बाद ही विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में सामान्य शुल्क और 10,000 रुपये विलंब शुल्क के अलावा अध्यक्ष या सचिव द्वारा तय किया अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा।

प्रशासनिक सुधार व बेहतर प्रदर्शन पर ही मिलेगी केंद्र सरकार से ग्रांट

राज्य ब्यूरो, जागरण। शिमला: प्रदेश में सरकारी विभागों को केंद्र सरकार से मिलने वाली पूंजीगत सहायता अब सीधे तौर पर प्रशासनिक सुधार और जमीनी प्रदर्शन (परफारमेंस) से जुड़ेगी। राज्यों के लिए विशेष सहायता पूंजीगत निवेश योजना के तहत ग्रांट हासिल करने के लिए विभागों को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाकर लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लानी होगी। योजना विभाग ने इस संदर्भ में प्रदेश के सरकारी विभागों को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

योजना विभाग के निर्देश के अनुसार सभी विभागों को अपनी जनसेवाओं को अनिवार्य रूप से आनलाइन और पारदर्शी बनाना होगा, ताकि आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और योजनाओं का लाभ सुगमता से मिले। इसके अलावा सरकारी स्तर पर फाइलों और नीतिगत मामलों के निष्पादन में गति लाने को कहा है।

हिमाचल सरकार को केंद्र की बुनियादी ढांचा वित्तपोषण योजना के तहत कुल 981 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। इसके अंतर्गत पहले चरण में 612 करोड़, दूसरे चरण में 88 करोड़ और हाल ही में तीसरे चरण के रूप में 281 करोड़ रुपये की राशि राज्य को मिली है। केंद्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूती देना है, लेकिन इसके लिए विभागों की कार्यकुशलता को पैमाना बनाया गया है।

विभागों को फाइलों के निपटारे सेवाओं को आनलाइन व पारदर्शी बनाने के निर्देश, केंद्र से प्रदेश को मिल चुके हैं 981 करोड़ रुपये

समय-समय पर होगा आडिट, केंद्र को जाएगी रिपोर्ट

विभागों के किए कार्यों और सुधारों की नियमित समीक्षा होगी। इसके लिए समय-समय पर कार्यों का आडिट और मूल्यांकन किया जाएगा। तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इसी के आधार पर तय होगा कि संबंधित विभाग को भविष्य में कितनी ग्रांट मिलेगी। जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होगा, उनकी केंद्रीय सहायता पर असर पड़ सकता है।



अब हर दिन सिर्फ एक सवाल, जीतना हुआ और भी आसान!

त्योहारों के इस मौसम में प्रतिदिन दैनिक जागरण पढ़ें, केवल एक सवाल का सही जवाब दें और जीतें आकर्षक इनाम!

क्विज संख्या : 44

दीवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की?

(क) चार (ख) पांच (ग) सात (घ) तीन

क्विज संख्या 42 के विजेताओं के नाम

अरुण	*****81007 गुरुग्राम	मोहित	*****45919 फरीदाबाद
आशीष	*****74376 सहारनपुर	पूर्णिमा	*****92300 बोकारो
आशुतोष	*****42126 फर्रुखाबाद	रजत	*****14327 गाजियाबाद
अविनाश	*****59468 इंदौर	राम	*****06245 रायबरेली
भीमेंद्र	*****08504 एटा	रीता	*****68398 ऋषिकेश
भूमिका	*****03640 देहरादून	रिया	*****41569 सोनीपत
गिरजा	*****87841 जबलपुर	रिया	*****62115 हल्द्वानी
ज्ञानेंद्र	*****79505 कानपुर	संदीप	*****37850 भोपाल
हिमांशु	*****68644 प्रयागराज	सुधीर	*****91474 गोरखपुर
कामिनी	*****55634 बरेली	सूरज	*****30562 वाराणसी
कार्तिक	*****34569 आगरा	सूरज	*****72860 रांची
कृष्णा	*****41212 मेरठ	सूरज	*****73893 पटना
महेश	*****10557 बदायूं	विनिता	*****53039 मुजफ्फरपुर
माही	*****33133 भागलपुर	बृजेश	*****70311 इटावा
मनोज	*****00955 सिरसा	मुकेश	*****66910 लखनऊ



आज के सवालों के जवाब देने के लिए स्कैन करें

क्विज संख्या 43 के उत्तर : (ख)

पढ़ते रहिए दैनिक जागरण

क्विज खेलने के लिए निःशुल्क एप्प डाउनलोड करना अनिवार्य

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

सीओ एसएएमः सोलन, शांडिल निवास समीप कल्याण भवन-173212 ई-मेल cosolanrecovery@pnb.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) एवं 8(6) के प्रावधानों को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
आम जनता तथा ऋणियों एवं गारंटरों को विशेष तौर पर एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्ति का बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संरचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी संबंधित ऋणियों एवं गारंटरों से बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर की नियत राशि की वसूली हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित अनुसार तिथि पर "जैसी है जहां है", "जो है जैसी है", और "जहां भी है जैसी है" आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के अंतर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / ऋणी/गारंटर का नाम एवं पता, खाता	सिक्योर्ड परिसंपत्तियों की अनुसूची / मोर्टगेज रखी गई अचल/चल सपत्तियों का विवरण/स्वामी का नाम (संपत्तियों के मोर्टगेजर)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि / बी) बकाया देय राशि / सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की तिथि / डी) कब्जे की प्रकृति- (प्रतीकात्मक/भौतिक)	ए) आरक्षित कीमत / बी) ईएमडी / सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय / सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ज्ञात भारों का विवरण
1.	पीएनबी कोटलानाला / श्री सन्नी गोयल पुत्र श्री सतिंदर गोयल / 1. श्री सन्नी गोयल निवासी गोयल निवास, गुरुद्वारा रोड, समीप गुरुद्वारा, वीपीओ चम्बाघाट, तहसील और जिला सोलन (हिप्र.) पिन:173213 (ऋणी) 2. श्री संजय मेहता पुत्र श्री सुंदर सिंह गांव बावरा बसाल पीओ चम्बाघाट, तहसील एवं जिला सोलन (हिप्र.) पिन:173213 (गारंटर)	श्री सन्नी गोयल पुत्र श्री सतिंदर गोयल के नाम में वर्ष 2012-2013 के लिए जमाबंदी के अनुसार मौजा कथेड, पटवार सर्कल सोलन, शहर II, तहसील एवं जिला सोलन (हिप्र.) में स्थित खाता/खतौनी सं. 267/299 मिन खसरा सं. 1125/875/779 माप 152 वर्ग मीटर में सम्मिलित भूमि पर निर्मित राजा कॉटेज के नाम से जाना जाता तीन मंजिला भवन में दो बैडरूम, रसोई एवं बाथरूम से युक्त बेसमेंट के साथ संपत्ति, क्षेत्र 54.40 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं पार्सल।	ए) 24.02.2026 / बी) रु. 9,43,689.84 (केवल नौ लाख तिरतालीस हजार छह सौ नवासी रुपये एवं चौरासी पैसे) तथा आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के साथ, वसूली को कम करके, यदि कोई की गई। / सी) 16.06.2026 / डी) प्रतीकात्मक	ए) रु. 19.00 लाख / बी) रु. 1.90 लाख / सी) रु. 0.50 लाख	26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे / ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों तथा निम्नलिखित आगामी शर्तों का विषय होगी: 1. संपत्तियां "जैसी है जहां है" तथा "जो है जैसा है" और "जहां है जैसी है" आधार पर बेची जाएंगी। 2. उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सिक्योर्ड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण ज्ञान के अनुसार दर्ज किया गया है परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी अथवा विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाईट https://baanknet.com/ पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से 26.11.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे को आयोजित की जाएगी। 4. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तें हेतु कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in पर पधारें।

दिनांक: 26.10.2026 (हस्ता./-) प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः सोलन पंजाब नैशनल बैंक, सिक्योर्ड क्रेडिटर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला:- पहली मंजिल, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकट हाइट्स), एप्पल मंडी के पास, भट्टाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006

ई-नीलामी बिक्री सूचना

विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए यहां स्कैन करें

अनुबंध-ई
अचल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[परिशिष्ट-II ए नियम 6(2) और 8(6) के साथ (अचल संपत्ति के लिए)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के नियम 6(2) और 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं, बंधककर्ता/बंधककर्ताओं और गारंटर/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां, जो प्रतिभूति लेनदार को गिरवी/बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें "**जैसा है जहां है**", "**जैसा है जो है**" और "**जो कुछ भी है**" के आधार पर नीचे उल्लिखित **खाते/खातों में देय राशि की वसूली के लिए बेचा जाएगा, किसी भी देय राशि की पहचान की जिम्मेदारी खरीदार की होगी, बैंक की नहीं।** उधारकर्ता/उधारकर्ताओं/बंधककर्ता/गारंटर/गारंटरों/प्रतिभूति आस्ति/देय राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	शाखा का नाम और उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का पता	अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई ज्ञात भार हो	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि और समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रत्याशित / भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय
1.	शाखा कार्यालयः धर्मशाला / उधारकर्ता/बंधककर्ताः- श्रीमती चंचला देवी पत्नी श्री राम सिंह, निवासी वार्ड नं. 8, ग्राम खोली, डाकघर सुनेहर, तहसील और जिला कांगड़ा - 176056। गारंटर(s):- श्री राम सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह, निवासी वार्ड नं. 8, ग्राम खोली, डाकघर सुनेहर, तहसील और जिला कांगड़ा - 176056।	खसरा नं. 308 और खतौनी 442 खसरा नं. 2154 में स्थित भूमि और निर्माण का पूरा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल 0-14-24 हेक्टेयर, जिसमें से 384/1424 हिस्से के अनुसार 0-03-84 हेक्टेयर भूमि, जो मोहल और मौजा खोली तहसील और जिला कांगड़ा, हि.प्र. में स्थित है, का बंधक विलेख पंजीकरण संख्या 1094/2017 तिथि 08.11.2017 के अनुसार श्रीमती चंचला देवी पत्नी श्री राम सिंह के नाम पर वर्ष 2014-15 की जमाबंदी में दर्ज है। सीमाएं:- उत्तरः कुहल और आरा मशीन; दक्षिणः निर्मल का घर; पूर्वः देश राज की खुली भूमि; पश्चिमः रास्ता।	रु. 18,30,092.41 (मूलधन) + रु. 3,14,938.28 (अप्रयुक्त ब्याज) + रु. 45,036.89 (ब्याज वापसी) + रु. 78,735/- (दंडात्मक ब्याज)। कुल देय राशिः- रु. 22,68,802.58 (बाईस लाख अड़सठ हजार आठ सौ दो रुपये और अट्ठावन पैसे मात्र) 18.10.2026 तक + वसूली तक आगे का ब्याज और शुल्क।	05.12.2026 / दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 24,37,000/- / रु. 2,43,700/- / रु. 50,000/-	बैंक का प्रतीकात्मक कब्जा	30.10.2026 से 04.12.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)
2.	शाखा कार्यालयः धर्मशाला / उधारकर्ता/बंधककर्ताः- श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नी श्री विपिन कुमार, निवासी अपर बरोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. - 176215। गारंटर(s):- श्री विपिन कुमार पुत्र श्री गोरखू राम, निवासी अपर बरोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. - 176215।	ग्राम अपर बरोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. के राजस्व एस्टेट में स्थित भूमि और उस पर निर्माण का पूरा हिस्सा। खसरा नं. 284 मिन खतौनी नं. 458 मिन खसरा नं. 1256/7 क्षेत्रफलः 00-01-72 हेक्टेयर, जैसा कि वर्ष 2007-08 की जमाबंदी और तकसीम हुक्मनामा नं. 2561 तिथि 24.10.2016 के अनुसार दर्ज है। लीन नोटिंग इंतकाल नं. 2599 आद रेहन तिथि 05.08.2022 श्रीमती अनुराधा पत्नी श्री विपिन कुमार के नाम पर दर्ज है। बंधक विलेख पंजीकरण संख्या 1037/2018 तिथि 29/05/2018। सीमाएं:- उत्तरः घर; दक्षिणः खुली भूमि; पूर्वः खुली भूमि और कुहल; पश्चिमः रास्ता।	रु. 13,84,945.35 (मूलधन) + रु. 83,771.35 (अप्रयुक्त ब्याज) + रु. 40,493.95 (ब्याज वापसी) + रु. 12,566/- (दंडात्मक ब्याज)। कुल देय राशि - रु. 15,21,776.65 (पंद्रह लाख इक्कीस हजार सात सौ छिहत्तर रुपये और पैंसठ पैसे मात्र) 18.10.2026 तक + वसूली तक आगे का ब्याज और शुल्क।	05.12.2026 / दोपहर 02:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक	रु. 17,02,000/- / रु. 1,70,200/- / रु. 50,000/-	बैंक का प्रतीकात्मक कब्जा	30.10.2026 से 04.12.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)
3.	शाखा कार्यालयः धर्मशाला / उधारकर्ता/बंधककर्ताः- श्री त्रिनदरजीत सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह, निवासी वार्ड नं. 2, ग्राम और डाकघर भगसू नाग, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि.प्र. - 176219।	खसरा नं. 15 और खतौनी 23 खसरा नं. 293/289, किता-1 में स्थित भूमि और उस पर निर्माण का पूरा हिस्सा, कुल क्षेत्रफल 0-